भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1494

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकी स्लीपिंग मॉड्यूल्स

†1494. श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों सहित देश के कई भागों से आतंकी समूह (जैसे आईएस/अल-कायदा) के सक्रिय होने की घटनाओं की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या आतंकी समूह अपना नेटवर्क स्थापित करने हेतु बेरोजगार और बेघर लोगों की भर्ती कर रहा है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आतंकी समूहों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और उनके कॉम्पलेक्स को तोड़ने हेतु क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख) : अबु बकर अल-बगदादी के नेतृत्व में इस्लामिक स्टेट (आईएस/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट (आईएसआईएल)/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस), जो फरवरी, 2014 में आल-कायदा से अलग हुआ था, भारत सहित वैश्विक स्तर पर युवाओं को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के मायाजाल का उपयोग कर रहा है।

अब तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र पुलिस ने-04, मध्य प्रदेश पुलिस ने 05, तेलंगाना पुलिस ने 06, तमिलनाडु पुलिस ने 03, कर्नाटक और राजस्थान पुलिस ने 01-01 और दिल्ली पुलिस ने 04 व्यक्तियों (हरिद्वार से 3 और रूडकी से 01) को गिरफ्तार किया है।

(ग) : एनआईए द्वारा दर्ज किए गए मामलों की जांच के दौरान यह पता चला है कि आईएसआईएस/आईएसआईएल प्रचार करने और आईएसआईएस/आईएसआईएल में शामिल होने के लिए युवाओं को भर्ती और प्रेरित करने के लिए अपनी विचारधारा का प्रचार करने हेतु विभिन्न इंटरनेट आधारित मंचों का प्रयोग कर रहा है।

(घ) : आसूचना और सुरक्षा एजेंसियां संभावित भर्तियों की पहचान करने और उन पर निगरानी रखने तथा आगे कार्रवाई करने के लिए साइबर स्पेस की गहन रूप से निगरानी करती है। आईएसआईएस/आईएसआईएल द्वारा उत्पन्न चुनौती का आकलन करने और इससे निपटने हेतु एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.08.2015 और 16.01.2016 को क्रमशः सभी संबंधित केन्द्रीय एजेंसियों और 12/13 राज्य सरकारों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। सरकार ने राज्यों को आईएसआईएस द्वारा उत्पन्न प्रारंभिक खतरों का सामना करने के प्रति भी सुग्राही बनाया है।